

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2017 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-**

---

- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।
2. निर्देश दिया गया कि विभाग में रिक्त पदों यथा उप सचिव, अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक आदि पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को प्रत्येक माह में एक बार अनिवार्य रूप से अनुरोध पत्र भेजा जाय। (अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)
  3. विभाग में रिक्त लिपिकीय सेवा के कर्मी यथा निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति हेतु अधियाचना (रोस्टर सहित) बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाय। (अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)
  4. विभाग में ई०-ऑफिस चालू करने हेतु तत्काल file movement लागू कराया जाय। इस हेतु सभी संचिकाओं को ई०-ऑफिस सॉफ्टवेयर में इंटी शीघ्र सुनिश्चित करायी जाय।  
(अनुपालन :- आई०टी० मैनेजर)
  5. विभागीय संवर्ग के कर्मियों यथा समूह 'घ' एवं निम्नवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। इस हेतु संबंधित संवर्ग के कर्मियों की सर्वप्रथम वरीयता सूची प्रकाशित की जाय। जिन कर्मियों का ACP/MACP लंबित है, उन्हें ACP/MACP देने हेतु प्रस्ताव संचिका उपस्थापित किया जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 11)
  6. बिहार नगर सेवा के कर्मियों के Cadre rule तैयार करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)
  7. DUDA एवं TCPO में कनीय अभियंता के स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)
  8. विभाग में सचिवालय सहायक के रिक्त पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के 'सहायक' पद से सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देश के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। (अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-1)
  9. राज्य योजना अंतर्गत स्वच्छता अनुदान मद में नगर निकायों को आवंटित की गयी राशि के विरुद्ध जिन नगर निकायों द्वारा प्रथम किस्त की राशि का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में प्राप्त हो गया है, उन्हें इस वर्ष के स्वच्छता अनुदान की राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)
  10. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत सभी नगर पंचायतों को वर्ष 2017-18 के लिए राशि आवंटित कर दी गयी है, लेकिन नगर परिषदों को अभी राशि आवंटित नहीं हो पायी है। निर्देश दिया गया कि इस योजनांतर्गत सभी नगर परिषदों (AMRUT योजना वाले नगर निकाय को छोड़कर) को राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)
  11. मुख्यमंत्री नाली-गली योजनांतर्गत पिछले वर्ष नगर निकायों को आवंटित की गयी प्रथम किस्त की राशि का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। जिन नगर निकायों द्वारा शत-प्रतिशत

उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में प्राप्त हो जाता है, उन्हें इस वर्ष राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)

12. Ease of Doing Business एवं AMRUT Reforms अंतर्गत प्रत्येक बिन्दु/मुद्दे पर प्रत्येक सप्ताह संचिका में प्रस्ताव अनिवार्य रूप से उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- श्री अरविन्द कुमार, का०अभि०/TCPO)

13. नवनिर्वाचित सभी महापौर/उपमहापौर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सभापति/उपसभापति के प्रशिक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दो दिवसीय कार्यशाला 15 से 30 जुलाई के बीच आयोजित की जाय। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री से तिथि निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित की जाय। कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों/नगरपालिका अधिनियमों की जानकारी हेतु booklet तैयार किया जाय। इस कार्यशाला में संबंधित सभी नगर निकायों को नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को भी भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाय।(अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

14. अन्य राज्यों के Advertisement rules का अध्ययन करके राज्य के नगर निकायों के लिए Advertisement rules तैयार करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय। (अनुपालन :- निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

15. पार्क विकास एवं संधारण नीति संबंधी संचिका पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजी गयी है, जो अभी तक विभाग में वापस प्राप्त नहीं हुआ है। इस संचिका के मामले का शीघ्र निष्पादन हेतु स्मार पत्र पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजा जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)

16. नगर निकायों में Community toilet एवं Mobile toilet के निर्माण हेतु निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकायों को आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :- श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

17. RERA, Affordable housing policy एवं CLSS के संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु बिल्डर्स एवं बैंकर्स कमिटी के साथ बैठक आयोजित करने के संबंध में प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :- सहायक नगर निवेशक)

18. निर्देश दिया गया कि Capacity building plan के आधार पर HFA अंतर्गत SLTC के लिए PMU का चयन, SBM अंतर्गत PMU का चयन तथा BGCMS अंतर्गत professional के चयन हेतु RFP इस सप्ताह के अंत तक अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाय।  
(अनुपालन :- संबंधित प्रभारी पदाधिकारी)

19. दानापुर, पटना (पूर्व के स्वीकृत 18 जोन के कार्य को छोड़कर) एवं मुजफ्फरपुर नगर निकाय के लिए पेयजल निश्चय योजनांतर्गत डी०पी०आर० बनाने का निर्देश पूर्व में बुडको एवं BRJP को दिया गया है, लेकिन अभी तक डी०पी०आर० तैयार कर विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

डी०पी०आर० शीघ्र तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने हेतु बुडको एवं BRJP को पत्र भेजा जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)

20. ए०डी०बी० संपोषित गया सिवरेज योजना के लिए Main STP हेतु जमीन की समस्या का निष्पादन हो गया है। निर्देश दिया गया कि इस योजना की स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-3)

21. मुख्य अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डूडा एवं नगर निकायों के निविदा के BOQ की काफी राशि जमा है, जिसे विभाग में जमा करने हेतु बजट शीर्ष उपलब्ध नहीं है।

निर्देश दिया गया कि BOQ का receipt बजट शीर्ष खोलने हेतु शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।  
(अनुपालन :- प्रशाखा पदाधिकारी-2)

22. भारत सरकार से स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करने हेतु संभवतः दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसकी समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव के साथ दिनांक 28.06.2017 को "PRAGATI" कार्यक्रम में किया जाना है, जिसका प्रतिवेदन भी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा माँग की गयी है। स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करने के संबंध में विभाग स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

निर्देश दिया गया कि स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय।  
(अनुपालन :- श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)

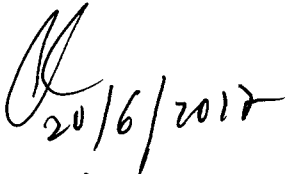
23. NULM, HFA, SBM योजना के प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत तक सभी बैंक खातों का PFMS कराना सुनिश्चित किया जाय। (अनुपालन :- योजना के प्रभारी पदा०)
24. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, Compliance report, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय। प्रशाखा पदाधिकारी-7 द्वारा Compliance report श्री अमितेष्, आई०टी० मैनेजर को नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगे एवं वे इस हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी-7 को यह भी निर्देश दिया गया कि CAG का Compliance report यदि ससमय नगर निकायों/एजेंसियों से प्राप्त नहीं होता है तो उसे उस जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी को समन्वय करके प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :- प्रशाखा पदा०-7 एवं आई०टी० मैनेजर)

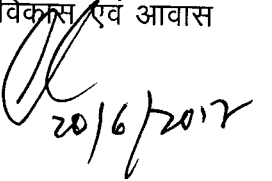
25. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
20/6/2017  
(चैतन्य प्रसाद),  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 4166 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 21/6/17

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/SPMG कोषांग/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
20/6/2017  
प्रधान सचिव

➤ **प्रशाखा-01 :-**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➤ **प्रशाखा-02 :-**

1. **सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था :-**

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे-छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।
- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर-टू-डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टेण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. **स्ट्रीट लाईट :-**

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

### 3. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

### 4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- (iii) सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।
- (iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

### ➤ प्रशाखा-03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
2. जल निसरण :-
  - इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।
3. शहरी परिवहन :-
  - उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने-जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
  - नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
  - शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांशों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया जाय।
4. सबके लिए शौचालय :-
  - हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
  - शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्तमान सूची में छूटे हुए हैं उनको सम्मिलित करने की कार्रवाई की जाए।
  - सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
  - वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
  - सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार-विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
  - वैसे आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

#### 5. सिवरेज की व्यवस्था :-

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

#### 6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :-

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

#### 7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सिवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
- (ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- (iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

#### ➤ AMRUT Mission से संबंधित कार्य :-

- (i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

#### ➤ प्रशाखा-04 :-

##### 1. सबके लिए आवास (शहरी) :-

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।

- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

##### 2. आवास योजना का MIS लागू करना।

##### 3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

#### 4. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

#### ● NULM से संबंधित कार्य :-

- शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

#### ➤ प्रशाखा-05 :-

##### 1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।

##### 2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग-अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा-5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :-

- नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।

#### 6. नगरीय प्रशासन :-

- "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
- नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
- शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
- पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
- विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनर्गठन पर विचार किया जाए।
- Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
- अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।

#### 7. सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-

- (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

#### ➤ प्रशाखा-6 :-

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

#### ➤ प्रशाखा-07 :-

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Double Entry Accounting System को Roll Out कराना।

#### ➤ प्रशाखा-8 :-

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

#### ➤ प्रशाखा-9 :-

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➤ **प्रशाखा-10 :-**

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।
- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक प्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➤ **प्रशाखा-11 :-**

1. **शहरों का सुनियोजित विकास :-**

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस-पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते हैं।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 :-**

- (i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

3. **TCPO कार्यालय का सुदृढीकरण।**

➤ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य :-**

- (i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
- (ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।